

संपादकीय

एक स्पष्ट संदेश

अपने चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने पहली बार दावा किया था कि अगर विपक्षी दल आम चुनाव जीतते हैं तो वे हिंदुओं के मंगलसूत्र समेत सारी संपत्ति उन लोगों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। यह भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक छिपा हुआ आरोप था। खुद प्रधानमंत्री के इस भाषण ने ज्यादातर पर्यवेक्षकों को चौंका दिया था। भारत के चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। बाद में उसने अपनी उदारता को चुनाव आयोग द्वारा “दोनों पार्टीयों के शीर्ष दो लोगों” को “नहीं छूने” के निर्णय के रूप में समझाया। चुनाव आयोग ने भले ही अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ लिया हो, लेकिन ठंडेंत के मतदाताओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, के उम्मीदवार को चुनकर भाजपा को भारी अंतर से हराया। मोदी के गृह राज्य गुजरात के बनासकांठ में उन्होंने मतदाताओं को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाया तो वह उनकी दो भैंसों में से एक को ले जाएगी। यहां कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकोर ने अजेय बढ़त हासिल की और अखिरकार सीट जीत ली। 2009 के बाद गुजरात में किसी भी लोकसभा सीट पर भाजपा की यह पहली हार थी। इन चुनावों के दौरान मोदी का अभियान न तो पिछले 10 सालों के उनके रिकॉर्ड के बारे में था और न ही अगले पांच सालों के लिए किसी बारे के बारे में। यह मुस्लिम विरोधी जहर से भरा था और निचली जाति के हिंदुओं में यह डर पैदा करने की कोशिश की गई थी कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आए तो उनके संवैधानिक लाभ और संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। 1992 में हिंदुत्व के पैदल सैनिकों द्वारा ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के स्थल पर राम मंदिर के निर्माण और मुस्लिम बहुल कश्मीर के प्रति अत्याचारी, सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ इस कथा से भाजपा को भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीटें और भाजपा के लिए 370 सीटों के नारे पर प्रचार करते हुए, मोदी की पार्टी ने बहुत कम जनादेश हासिल किया है। जब मैं यह लिख रहा हूँ, तब भी भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर है और इसलिए सरकार बनाने के लिए दो अस्थिर सहयोगियों – नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी – पर निर्भर है। जब से मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से भाजपा उनके नेतृत्व में हुए चुनावों में अपने दम पर भारी बहुमत पाने में कभी विफल नहीं हुई है। यह लोकसभा चुनाव एक अपवाद है। इसलिए यह सरकार चलाने के लिए सहयोगियों के साथ समझौता करने के मोदी के कौशल का परीक्षण होगा। हो सकता है कि अब वह एक-पार्टी, एक-नेता वाली सरकार का नेतृत्व न करेये यह अपने स्वयं के दबावों के साथ एक गठबंधन सरकार होगी। ये कारक तुरंत सामने आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जल्द ही इनके सामने आने की संभावना है। राजनीति की यही प्रकृति है। भले ही उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए, लेकिन कल के परिणाम के बाद मोदी एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कमजोर हो गए हैं। उन्हें अपनी वैधता एक विशाल जनादेश से मिलती है, जिसका श्रेय अक्सर कई बाधाओं के बावजूद चमत्कारिक चुनावी जीत हासिल करने की उनकी क्षमता को दिया जाता है। एक बार जब वह चमक फीकी पड़ने लगती है, जैसा कि उनकी अपनी वाराणसी लोकसभा सीट पर उनकी जीत के कम अंतर से देखा जा सकता है, तो पार्टी और बड़े संघ परिवार के भीतर सवाल उठना लाजिमी है। पिछले दशक में निर्णायक जनादेश के वजन के कारण जो तनाव दब गया था, वह भड़क सकता है और अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। उनका प्रभामंडल कम हो गया है। जब ऐसा होता है, तो प्रभामंडल अक्सर कहावत के अनुसार फंदा बन जाता है। यह चुनाव परिणाम उनके मुस्लिम विरोधी अभियान को पूरी तरह से खारिज करता है या नहीं, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यह मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का स्पष्ट खंडन है। उनकी आर्थिक नीतियां भारतीयों के विशाल जनसमूह, विशेष रूप से गरीबों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए एक आपदा थीं। 2014 के बाद से ६ वर्ष और आय असमानता में तेजी से वृद्धि हुई है, बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊर्चाई पर है और मूल्य वृद्धि आम लोगों का नुकसान पहुंचा रही है। मीडिया में प्रकाशित कई सर्वेक्षणों में ये बातें दर्ज की गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है, क्योंकि उसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धर्मीकरण करने की अपनी क्षमता के कारण चुनावों में जीत का भरोसा था। लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत अन्य राज्यों ने भाजपा की योजना को विफल कर दिया है। मोदी को पूँजीवाद में लिप्त और गरीबों के दर्द के प्रति असंवेदनशील देखा गया। 80 छक्रोड़ भारतीयों को पांच किलोग्राम मुफ्त राशन देने की योजना अब उपयोगी नहीं रही और लोग इसके बदले नौकरी की मांग कर रहे हैं। सैनिकों के लिए अल्पकालिक संविदा योजना अनिन्पथ बेरोजगारी की चुनौती और शिकायतों को सुनने के प्रति सरकार की अनिच्छा का उदाहरण है। उत्तर भारत में युवा – खासकर निचली और मध्यम जातियों के – जो सेना के लिए पारंपरिक भर्ती मैदान बनाते हैं, ने मतदान केंद्र पर अपनी बात रखी है। बेरोजगारी एक ऐसी चुनौती है जिसका समाधान नहीं किया

आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़- और प्रकृति से होता खिलवाड़

1

दुनिया प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा देख रही

आदित्य

चुनावों के कारण लगभग दो ने के अंतराल के बाद जैसे-जैसे र शासन की ओर लौट रहा है, इश नीति के मुद्दे क्षितिज पर छाए गए। भारतीय चुनावी कैलेंडर के इन दुनिया रुकी नहीं है। कुछ नों में, इसे भारत ने भी पहचाना दिल्ली ने ईरान में रणनीतिक से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह विकसित करने के लिए 10 साल ममझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि द्वितीय नीति निर्माता पड़ोसी राज्यों दौरा करना जारी रखते हैं। राष्ट्रीय माहौल चुनावीपूर्ण है, या भर में कई संकट मंडरा रहे हैं। इस वैशिक जटिलता को नेविगेट ना नई सरकार के लिए मिकता होनी चाहिए। दुनिया व शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पर बनी बहुपक्षीय व्यवस्था इस स्थिति को संबोधित करने लिए उपयुक्त नहीं है। वैशिक याएँ उस समय कार्रवाई में गायब आवश्यकता है। कठार शक्ति वाला आ गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्र राज्यों की मिली बड़े और छोटे, परिवर्तन की तीव्रता से जूझ रहे हैं। भारतीय विदेश ने व्टप्य-19 चंदकमउपव के लिए से अशांत अवधि को काफी प्रभाव दंग से प्रबंधित किया है। महाभारत के चलते आर्थिक तनाव जारी है रू वैशिक अर्थव्यवस्थाओं अव्यवस्था

सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई है। भारत की आर्थिक कहानी बेहतर रही है — यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रगति अर्थव्यवस्था है — लेकिन चुनावीनियां अभी भी विकट हैं। भारत की बहुआर्थिक ताकत ने नई दिल्ली वैशिक मंच पर एक नई आवाज दी है। इसका इस्तेमाल न केवल 35 नेतृत्व के लिए एक मामला बनाने के लिए किया गया है, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने के लिए भी किया गया है। चीन, विश्व

ओंकार अपस्त्रीय दुम्रा, व्रता गोति बाद नावी नारी रहा में और थल वैथिक नेया मुख तेयाँ ढ़ती को दी अपने नाने बल के रुस और पश्चिम भी ग्लोबल साउथ को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भारत के नेतृत्व की परीक्षा होगी कि वह एक ऐसे मुद्दे की वकालत को जारी रखे, जिसकी अब बहुत ज्यादा मांग है। फिर भी, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि मौजूदा वैश्विक संरचनाएँ विकासशील दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। भारत की नई व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति चुनौती नई दिल्ली के प्रति चीन का विरोधी रवेया जारी रहेगा। सीमा विवाद, जो 2020 में नाटकीय रूप से बढ़ गया था, अभी भी अनसुलझा है और दोनों पक्षों की स्थिति सख्त हो गई है। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और ताइवान जलउत्तरमध्य में बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता के कारण यह संभावना नहीं है कि वह हिमालयी सीमा पर अपना रुख बदलेगा। चीन और भारत के बीच टकराव केवल सीमा को लेकर नहीं है। यह एक क्षेत्रीय और

A photograph of Prime Minister Narendra Modi sitting at a desk, resting his chin on his hand in a thoughtful pose. He is wearing a white kurta and a black shawl. The background is a wooden panel wall.

आकर्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा, जिस पर भारतीय नीति निर्माताओं को जवाब देना होगा। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है जो अस्थिर स्थिति में है। दुनिया के अधिकांश देशों की तरह भारत भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी का मतलब है कि नई दिल्ली को उनकी अप्रत्याशितता के इर्द-गिर्द काम करना होगा। उनके कार्यकाल का पिछला कार्यकाल उतार-चढ़ाव भरा रहा, भले ही भारत उनके साथ काम करने का तरीका खोजने में कामयाब रहा। लेकिन पुराने ढर्रे के फिर से काम करने की संभावना नहीं है और नई दिल्ली को और अधिक उथल-पुथल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की विदेश नीति के मोर्चे पर चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। एक कठिन वैश्विक माहौल का मतलब है कि भारतीय कूटनीति और सरकार को चुनौती का सामना करना होगा।



विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी करके चीन के उदय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इंडो-पैसिफिक में एक अधिक शक्तिशाली मंच के रूप में क्वाड का पुनरुत्थान इसका एक उदाहरण है। वैश्विक विचार-डन के परिणामस्वरूप रूस और चीन के पारंपरिक संबंधों को चुनौती मिल रही है। नई दिल्ली ने रूस-यूक्रेन युद्ध को वैश्विक मानदंडों के इर्द-गिर्द अपनी प्रतिक्रिया तैयार करके और सीधे रूस को दोषी न ठहराकर प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन चीन के प्रति रूस का

विकासशील दक्षिण के लिए आंकड़ों का विश्लेषण

वनाद मीरे फ

चाज जितना बदलता ह, उतना वे एक जैसी रहती हैं। यह बात भले ही बड़े छंजपदवंस कंजम के लिए सही न हो, उन दक्षिण का चुनावी परिदृश्य नाव के बड़े परिदृश्य के बीच तरता की भावना को दर्शाता ने रंतरता और बदलाव के परस्पर व को ध्यान में रखते हुए— 9 की तुलना में, राज्य स्तर पर भाजपा और एनडीए, कांग्रेस और इत के दलों के साथ—साथ अन्य दलों के बोट शेयर और दों की संख्या में बदलाव हुआ तमिलनाडु में, जहां भाजपा ने कड़ज के बिना जाने का फैसला लिया, वह एक भी सीट जीतने में ल रही, लेकिन साथ ही, उसने ने दम पर लगभग 11 प्रतिशत हासिल किए। राज्य ने कड़ज कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंध को लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। इसी तरह, पड़ोसी केरल में, के भाजपा ने पहली बार एक उसभा सीट जीती और 2019 में

रूप
4 में
कुल
हा।
मुला
023
ममत
र्शन
सने
ं से
कि,
14
वहीं,
टोटों
टोटों
ा 6
भागे
वीर
है।
पनी
दी,
हो
20
हो
सच
पनी

साटा का सब्जा तान से बढ़ाकर आठ लोकसभा सीटें कर लीं और इसके बोट शेयर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहां सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति को हुआ, जो एक भी सीट नहीं जीत पाई और अपने बोटों का लगभग 25 प्रतिशत खो दिया। अगर तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी के चुनावी हाशिए पर जाने की बात है, तो आंध्र की कहानी दो राज्य दलों, लैंड ब्वदहतमे और तेलुगु देशम पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा की गाथा बनी हुई है, जहाँ दो राष्ट्रीय दल, भाजपा और कांग्रेस, हाशिए पर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 22 सीटें जीतने वाली वाईएसआर कांग्रेस इस बार सिर्फ चार सीटें ही जीत सकी, जबकि उसका बोट शेयर 50 प्रतिशत से गिरकर 40 प्रतिशत पर आ गया – एक बड़ी गिरावट। दूसरी ओर, टीडीपी का सत्ता से एक दशक का अंतराल समाप्त हो गया क्योंकि इसने राज्य विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया,

साथ हा एनडीए का सोटा का संख्या को 21 सीटों तक पहुँचाया। कुल मिलाकर, जबकि दक्षिणी राज्यों में एनडीए की सीटें 2019 में 30 सीटों से बढ़कर 2024 में 41 सीटों पर पहुँच गईं, भाजपा की कुल सीटें 29 पर ही बनी रहीं। फिर भी, भाजपा की सीटों की संख्या में स्थिरता का एक निहितार्थ भी है। अब भाजपा केवल कर्नाटक में ही नहीं, बल्कि सभी दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारत ब्लॉक के दृष्टिकोण से, दक्षिण में बहुत लाभ हुआ है। 2019 में उनकी सीटों की संख्या 58 से बढ़कर 2024 में 74 हो गईय कांग्रेस ने भी अपनी सीटों की संख्या 27 से बढ़कर 40 कर ली। जबकि दक्षिणी राज्यों की अपनी विशिष्टताएँ हैं, इस क्षेत्र में समग्र प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों में प्रवृत्तियों की पुष्टि करती है। यदि तेलंगाना और आंध्र भाजपा के पक्ष में स्विंग राज्य के रूप में उभरे, तो कर्नाटक ने पार्टी के वाहन को नुकसान पहुँचाया, और केरल और तमिलनाडु को अब भविष्य के क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए 2024 का चुनावी फैसला दक्षिण में राजनीतिक गतिशीलता में व्यापक बदलाव प्रस्तुत करता है। दो स्पष्ट रुझान हैं। पहला, तीन राज्य — कर्नाटक, केरल और तेलंगाना — क्षेत्रीय दलों की कीमत पर राष्ट्रीय दलों को पुरस्कृत कर रहे हैं। बीआरएस और जेडी(एस) की दुखद स्थिति इसका उदाहरण है। यह बदलाव दक्षिणी राज्यों के एकीकरण अभियान को भी दर्शाता है, जहाँ वे उन पार्टियों को छोड़ रहे हैं जो कभी क्षेत्रीय पहचान और हितों के समर्थक थे। हालाँकि, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक अलग तस्वीर पेश करते हैं जहाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ या तो हाशिये पर हैं या प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे हैं। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच सत्ता में वारी—वारी से आने वाला दौर आंध्र में निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु में डीएमके एक आंध्रपत्य बना हुआ है जबकि एआईएडीएमके ने दिखाया है कि

उसके पास अभी भी एक मजबूत वोट शेयर है। एआईएडीएमके के वोटों को अपने पाले में लाने में भाजपा की विफलता राज्य के क्षेत्रीय- पार्टी- केंद्रित चरित्र को बनाए रखती है। इसके अलावा, तमिलनाडु में भाजपा की 2024 की रणनीति, जहाँ पार्टी ने एआईएडीएमके के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का फैसला किया, को कई लोगों ने एक साहसिक कदम माना, जो चुनावी लड़ाई को एक वैचारिक लड़ाई बनाने के उनके इरादे को दर्शाता है। 11 प्रतिशत वोट जीतकर, हालांकि पार्टी भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित महसूस कर सकती है, लेकिन यह फैसला तत्काल दौड़ में पार्टी के लिए चीजों को अस्पष्ट बनाता है। जबकि दक्षिणी राज्यों की अपनी अलग-अलग विशिष्टताएँ हैं, यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के अव्यवस्थित ढाँचे से बहुत मेल खाता है। इसलिए, भारतीय राजनीति को उत्तर बनाम दक्षिण के द्विआधारी रूप में तैयार किया जाता है।

एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों पर विचित्र विवाद

2024 वर्ष

कौन सत्ता में आएगा, जब तीक्ष्णत नतीजों की घोषणा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रूपी है, के साथ—साथ विपक्षी दलों नागर्य का फैसला करेंगे। लेकिन तत्विक मतागणना से पहले, जट पोल की भविष्यवाणियों पर नाटक और विवाद देखा गया जिसमें श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लिए भारी जीत की बात गई है। यह आश्चर्यजनक से एक विवाद में पड़ गया है, जिकि विपक्ष ने निष्कर्षों को खारिज करने की कोशिश की और जोर र कहा कि वे सत्ता में आने की में बहुत आगे हैं। विपक्ष द्वारा तरह का जवाबी हमला एक शिवसेना के संजय राउत, जो एक पत्रकार है, ने दावा किया विपक्षी आई.एन.डी.आई.ए. सखेल में पूरी तरह से शामिल और कुल 543 सीटों में से 2 सीटें जीत सकता है, जिसने बात को लेकर बहुत उत्सुकता दी है कि आगे क्या होने वाला उनका दावा आई.एन.डी.आई. नेताओं की बैठक के एक दिन आया। एरिजट पोल के पूर्वानुमान से यह स्पष्ट है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी (आई.एन.डी.आई.ए.) के मुकाबले लोकसभा की दौड़ में काफी उत्तर है, जिसका एक मुख्य घटक कांगड़ा है। वास्तविक संख्याएँ दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र में एरिजट प

है। खुद कि मूह में है 295 इस बढ़ा है। ए. बाद जानों तृत्यार्टी बले आगे ग्रेस के गोल,

के अभ्यासों के कारोबार पर स्वीकृतिधर्मीकृति की मुहर लगाएँगी। परिणाम से यह पता चलने की उम्मीद है कि मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, प्रतिद्वंद्वी पक्षों के लिए क्या गलत हुआ और किस चीज ने उनकी मदद की। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हाल ही में समाप्त हुआ अभियान प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे कठिन था, जो 2002 में गुजरात के दिनों से लगातार जीत की लय में हैं। यह चुनाव इतिहास में मोदी के लिए सबसे पेचीदा चुनाव के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि वे कई चुनावी लड़ाई के नायक हैं, जो इस बार अधेरे में लड़ रहे थे। कई टिप्पणीकारों ने दावा किया था कि मोदी इस बार बस से चूक

की घोषणा में देरी की थी, जो उनके अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जनवरी में होनी चाहिए थी। दो महीने लंबा चुनाव कार्यक्रम भी भाजपा के लिए थोड़ा परेशानी भरा लग रहा था, जिसका उद्देश्य श्री मोदी को प्रचार के लिए अधिक समय देना था, लेकिन कथा के अभाव में यह उनके लिए बहुत थकाऊ लग रहा था। यदि एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं, तो विपक्ष के लिए सबक यह है कि वे उन राज्यों में एक लड़ाकू ताकत बन सकते हैं, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत की है और भयंकर लड़ाई में हाथ मिलाया है, और यही बात राष्ट्रीय स्तर पर भी दोहराई जानी चाहिए। एग्जिट पोल

है। इसके अलावा, श्री मोदी और अमित शाह दोनों ही चुनाव लड़ने के मामले में सख्त कार्यपालक माने जाते हैं। हालांकि, भाजपा का एक वर्ग जोर देकर कहता है कि धर्मीकरण के खेल में श्री मोदी माहिर हैं। उनके हिंदू-मुस्लिम बयानबाजी ने चुपचाप बहुसंख्यकों को लामबंद कर दिया है और हिंदुत्व कार्ड को कार्रवाई में देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जाति जनगणना के तर्क को नहीं मानता है, जो उन्हें लगता है कि अपनी समाप्ति तिथि पार कर चुका है। मोदी के प्रशंसक नहीं माने जाने वाले एक समाचार वेबसाइट के रिपोर्टर ने जोर देकर कहा कि उन्होंने अभियान के दौरान जो देखा।

आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़- और प्रकृति से होता रिलवाड़

लिलि

भारत की इस धरती पर मौजूद नमस्त जीवधारियों में केवल हम नुष्ट ही है जो कि विवेकशील आज हमारी प्रकृति खून के आंसू रो रही है कि काश उसने मनुष्ट को विवेकशील ना बनाया होता । आज यदि आधुनिकता वैश्वीकरण और खुद को सभ्य अपने हिस्से में ई धरती को कूड़े का ढेर बना दिया । यदि आज हमारा दाम आज घुट रहा है तो इसका कारण हम स्वयं हैं । एक आपदा के बाद दूसरीआपदा और महामारी के आने का इंतजार करते हम मनुष्ट, वाकई हम कितने ही सभ्य क्यों न हो जाए पर प्रकृति के प्रकोप के आगे सर विकास और सारी सभ्यता शून्य सिद्ध हो जाती है उसे दिन हमें यह एहसास होता है कि हम मनुष्ट प्रकृति की इस सजा के काबिलऔर हकदार हैं । एक व्यक्ति की बात होती तो यायद पृथ्वी भी सब्र कर लेती थीने के खून के आंसू रोते हैं पर हम यह भूल जाते हैं कि हमने ही यहां के पेड़ काटे, यहां की नदियों का दोहन किया, यहां के सुमुद्र को गंदा किया, यहां के हवा को प्रदूषित किया, पूरी पृथ्वी को पूरी अपने हिस्से में ई धरती को कूड़े उद्योगों और मशीनों की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है अनाज की/प्राकृतिक संसाधनों की.. जो इसी पृथ्वी के सीने को चीरकर हम प्राप्त करते हैं । जीवन को चलाने के लिए हवा की जो इसी प्रकृति में पौधों के द्वारा छोड़ी गई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त करते हैं आवश्यकता है पानी की जो यही के पहाड़ों से निकली हुई नदियों झीलों और झरनों से प्राप्त होता है और यदि इससे आगे बढ़े तो इसी पृथ्वी के सीने में छेद करके अत्याधिक रूप से नदियों की जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या का दबाव और प्राकृतिक संसाधनों में पानी की कमी इसी प्रकार जारी रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब पानी कैप्सूल के रूप में हमें मिलेगा । जनसंख्या का बढ़ता दबाव, सीमित संसाधनों की उपलब्धता प्राकृतिक दोहन की एक सीमा आज मनुष्ट को विवश करती है कि वह समझे कि यदि उसे आने वाली पीढ़ियां के लिए हवा पानी और भजन इस प्राकृतिक से लेना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या अवधारणात्म विकास की अवधारणा को समझना ही होगा । विकास की अंधी दौड़ को थोड़ा रुक कर, थोड़ा भावनाओं युक्त होकर कहें पेड़ों को बिना कटे विकास कैसे किया जाए इसकी कोई योजना नहीं है हजारों साल पुराने पेड़ सड़क के चौड़ीकरण हाईवे या विभिन्न प्रकार के रास्तों के निर्माण के लिए पेड़ों की संख्या के रह जाती है । पर्यावरण दिवस पर यदि पेड़ लगाए भी जाते हैं तो करोड़ों की संख्या में जो सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए या आंकड़ों के लिए तो अच्छा लगता है पर उनमें से कितने पेड़ एक साल तक भी जीवित रहते हैं यह देखने वाला कोई नहीं । इतने पेड़ सोशल मीडिया और फेसबुक टिवटर में दिखाने के लिए लगा दिए जाते हैं बहुधा तो स्थान का भी अभाव हो जाता है । आदमी कहाँ पेड़ लगाये? यह एक दिन पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तय कर लिया जाता है । किसी भी सरकार की वन्य जीव संरक्षण या कहें पेड़ों को बिना कटे विकास कैसे किया जाए इसकी कोई योजना नहीं है हजारों साल पुराने पेड़ सड़क के चौड़ीकरण हाईवे या विभिन्न प्रकार के रास्तों के निर्माण के लिए पेड़ों की संख्या आम आदमी को कब तक दोष दिया जाएगा दोषी तो वह नीति निर्माता है जो अरबो रुपए का बजट पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जारी तो करते हैं पर हर वर्ष वह कितना हकीकत में खर्च होता है, जमीनी हकीकत क्या है यह आप और हम सभी जानते हैं । काश हमारी सरकारों ने कोई आधारभूत संरचना व योजना तैयार की होती तो आज यह देश जहां मौसम की विविधता पाई जाती है सर्दी गर्मी और बरसात हर प्रकार की विविधता है प्रकृति शांति और सुकून है । आज हम कभी ज्यादा गर्मी पड़ने का डर कभी ज्यादा सर्दी पड़ने का डर, कभी ज्यादा सर्दी बरसात होने का डर और इस डर का निदान सिर्फ एक है कि हमारे पास वृक्ष, पेड़, पौधों की संख्या

